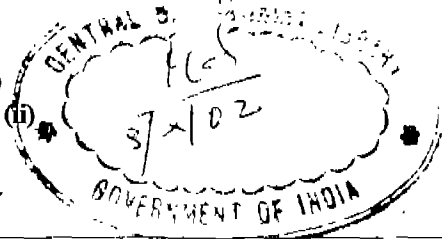




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2002/वैशाख 10, 1924

No. 400]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2002/VAISAKHA 10, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

( नौवहन पक्ष )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2002

का.आ. 473(अ).—दिनांक 01-02-2002 की असाधारण अधिसूचना सं. का.आ. 149(अ) के द्वारा बी. ए. डिसिल्वा एवं अन्य बनाम संघ सरकार एवं अन्य (2001 की रिट याचिका सं. 1553) के मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 8 अक्टूबर, 2001 के आदेशानुसार श्रीमती प्रतिमा उमरजी, प्रधान सचिव, कानून एवं न्याय विभाग विधायी और संसदीय विभाग, महाराष्ट्र सरकार की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायाधिकरण के क्रम में केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण के कार्यकाल को एतद्वारा 30-4-2002 से आगे तीन माह और बढ़ाती है। उल्लिखित अधिसूचना के साथ अनुबंधित सौंपे गए कृत्य तथा निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[ फा. सं. एस. आर.-11014/2/2001-एम.ए. ]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Shipping Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2002

S.O. 473(E).—In continuation of Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 149(E) dated 01-02-2002 constituting one Man Tribunal under the chairmanship of Mrs. Pratima Umarji, Principal Secretary, Law & Judiciary Department (Legislation) & Parliamentary Affairs Department, Government of Maharashtra in the matter of B.A. D'Silva & others *Versus* Union of India & others (Writ Petition No. 1553 of 2001) in accordance with the Mumbai High Court Order Dated 8-10-2001, the Central Government grants further extension of time to the Tribunal for 3 months beyond 30th April, 2002. The Terms of Reference and other terms and conditions annexed to the said notification will remain unchanged.

[ F.No. S.R.-11014/2/2001-M.A. ]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

